

करेंट अफेयर्स

छत्तीसगढ़

(संग्रह)



मार्च
2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

छत्तीसगढ़	3
➤ छत्तीसगढ़ बजट	4
➤ छत्तीसगढ़ में साइबर धोखाधड़ी रिपोर्ट	6
➤ छत्तीसगढ़ में महिला पंचायत की जगह प्रॉक्सी शपथ	7
➤ नई माओवादी पुनर्वास नीति	8
➤ सुदूर सीआरपीएफ बेस पर पहला मोबाइल टावर	9
➤ कांग्रेस घाटी राष्ट्रीय उद्यान	10
➤ छत्तीसगढ़ खनिज राजस्व में वृद्धि	12
➤ बस्तर में 30 माओवादी मारे गए	13
➤ 'माओवाद मुक्त' पंचायतों के लिये विशेष प्रोत्साहन	14

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



SCAN ME

UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



SCAN ME

दृष्टि लर्निंग
ऐप



SCAN ME

नोट :

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में माओवादियों से मुठभेड़

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में माओवादी मारे गए।

मुख्य बिंदु

- **माओवादी हताहत:**
 - ◆ नवीनतम मुठभेड़ के कारण संघर्ष प्रभावित बस्तर क्षेत्र में 2025 के पहले 60 दिनों में मारे गए माओवादियों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है।
 - ◆ सुकमा, जहाँ मुठभेड़ हुई, बस्तर क्षेत्र के सात जिलों में से एक है।
 - ◆ इसके अतिरिक्त, सुरक्षा बलों ने बस्तर के बाहर स्थित गरियाबंद जिले में मुठभेड़ों में 17 माओवादियों को मार गिराया।
 - ◆ छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025 में मारे गए माओवादियों की कुल संख्या 84 है।
 - ◆ वर्ष 2024 में नक्सल विरोधी अभियानों (ANO) के दौरान सुरक्षा बलों ने राज्य में 219 माओवादियों को मार गिराया था।
- **सुकमा मुठभेड़ का विवरण:**
 - ◆ पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया।
 - ◆ इस अभियान में छत्तीसगढ़ पुलिस के ज़िला रिज़र्व गार्ड (DRG) और केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) की एक विशिष्ट इकाई कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन (CoBRA) के जवान शामिल थे।

ज़िला रिज़र्व गार्ड (DRG)

- ज़िला रिज़र्व गार्ड (DRG) छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा से निपटने के लिये वर्ष 2008 में स्थापित एक विशेष पुलिस इकाई है।
- इसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मी शामिल होते हैं जो प्रभावित जिलों में कार्य करते हैं, माओवादी विरोधी अभियान चलाते हैं, तलाशी और जब्ती करते हैं तथा खुफिया जानकारी जुटाते हैं।
- DRG माओवादी विद्रोह का मुकाबला करने के लिये केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) जैसे अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कार्य करता है।

केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF)

- CRPF की स्थापना वर्ष 1939 में रियासतों में राजनीतिक उथल-पुथल और अशांति के जवाब में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- वर्ष 1949 में इस बल का नाम बदलकर **केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल** कर दिया गया।
- तत्कालीन गृह मंत्री **सरदार वल्लभ भाई पटेल** ने CRPF के लिये एक बहुआयामी भूमिका की कल्पना की थी, ताकि इसके कार्यों को एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की उभरती आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जा सके।

CoBRA

- यह भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष ऑपरेशन इकाई है जो गुरिल्ला रणनीति और जंगल युद्ध में कुशल है। मूल रूप से नक्सली आंदोलन का मुकाबला करने के लिये स्थापित किया गया था।
- CoBRA को विषम युद्ध में शामिल विद्रोही समूहों से निपटने के लिये तैनात किया जाता है।

छत्तीसगढ़ बजट

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने राज्य **विधानसभा** में 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया और **लालफीताशाही** को कम करने तथा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के उपायों पर प्रकाश डाला।

- उन्होंने सरकार के दृष्टिकोण को उजागर करने के लिये संक्षिप्त नाम **GATI (सुशासन, बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास में तेज़ी)** भी पेश किया।

मुख्य बिंदु

- **सुधार का प्रयास:**
 - ◆ सरकार ने **कारोबार में सुगमता** को बढ़ावा देने के लिये पहले चरण में 20 विभागों में 216 सुधारों को लागू करने का लक्ष्य रखा है।
 - ◆ व्यापार सुधार कार्य योजना का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और नियमों को सरल बनाना है।
 - ◆ धोखाधड़ी को रोकने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा कागज़ रहित और चेहरा रहित प्रक्रियाओं को सक्षम करने के लिये विभिन्न स्तरों पर **डिजिटलीकरण** पहल लागू की जा रही है।
 - ◆ सरलीकरण के लिये पासपोर्ट कार्यालय की प्रक्रियाओं के समान एक नई भूमि पंजीकरण प्रणाली शुरू की जाएगी।
 - ◆ परिसंपत्तियों के त्याग और विभाजन के लिये लगने वाले उच्च शुल्क के स्थान पर 500 रुपए का निश्चित शुल्क लगेगा, जिससे राजस्व विवादों को रोकने में मदद मिलेगी।
- **क्षेत्रीय पहल:**
 - ◆ शिक्षा, ग्रामीण विकास, शहरी बुनियादी ढाँचे और सुरक्षा के लिये नई पहल की घोषणा की गई।
 - ◆ विशेष योजनाएँ बस्तर और सरगुजा जैसे सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में **परिवहन और मोबाइल कनेक्टिविटी** पर केंद्रित होंगी।
- **बजट अनुमान एवं वृद्धि अनुमान:**
 - ◆ आगामी वित्त वर्ष के लिये **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)** 6,35,918 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो 2024-25 के 5,67,880 करोड़ रुपए के अनुमान से 12% अधिक है।
 - ◆ पूंजीगत व्यय 18% बढ़कर 22,300 करोड़ रुपए से 26,341 करोड़ रुपए हो गया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

● बुनियादी ढाँचा और सड़क योजना 2030:

- ◆ बजट में सड़क निर्माण के लिये 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो राज्य के गठन के बाद से सबसे अधिक है।
- ◆ सड़क योजना 2030 राज्य की राजधानी को जिलों से जोड़ेगी तथा जिलों और विकास खंडों के बीच संपर्क में सुधार करेगी।

● मोबाइल कनेक्टिविटी और परिवहन:

- ◆ मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना से दूरदराज के क्षेत्रों में सेलफोन कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
- ◆ मुख्यमंत्री परिवहन योजना ग्राम पंचायतों से लेकर ब्लॉकों और जिलों तक परिवहन सेवाओं को वित्तपोषित करेगी, जिससे कम घनत्व वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की कमी दूर होगी।

● प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक विकास:

- ◆ बजट आवंटन में शामिल हैं:
 - न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण
 - राज्य डाटा सेंटर का निर्माण
 - आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियाँ
- ◆ उद्योग का बजट परिव्यय पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना बढ़ गया है।

● पेंशन फंड एवं वित्तीय स्थिरता:

- ◆ एक नया पेंशन फंड सरकारी कर्मचारियों के लिये सुरक्षित पेंशन सुनिश्चित करता है, जो भारत में अपनी तरह की पहली पहल है।
- ◆ छत्तीसगढ़ विकास एवं स्थिरता कोष से राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
- ◆ यह पेंशन निधि 2039 के बाद के राजकोषीय बोझ से संबंधित चिंताओं का समाधान करती है, जब राज्य के निर्माण के बाद भर्ती किये गए अधिकांश कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

● सहकारिता एवं शिक्षा:

- ◆ 500 नई सहकारी समितियाँ स्थापित की जाएंगी।
- ◆ राज्य में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना की जाएगी।

● कल्याणकारी योजनाएँ एवं राजकोषीय प्रबंधन:

- ◆ कृषक उन्नति योजना (किसानों के लिये) को 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ।
- ◆ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को 8,500 करोड़ रुपए मिले।
- ◆ पात्र विवाहित महिलाओं के लिये नकद सहायता योजना, महतारी वंदन योजना को 5,500 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।
- ◆ राजकोषीय घाटा GSDP के 2.90% से बढ़कर 2.97% हो गया है।
- ◆ किसी नए कर की घोषणा नहीं की गई, लेकिन 1 अप्रैल, 2025 से पेट्रोल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) 1 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया जाएगा।

महतारी वंदना योजना

- इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करना, उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और परिवारों में उनकी निर्णायक भूमिका को मजबूत करना है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं सहित 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी विवाहित महिलाएँ इस योजना से लाभ पाने के लिये पात्र हैं।
- छत्तीसगढ़ में पात्र विवाहित महिलाओं को **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** के माध्यम से प्रति माह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

- शुभारंभ: “सभी के लिये आवास” के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये, पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना इंदिरा आवास योजना को 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में पुनर्गठित किया गया।
- संबंधित मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- उद्देश्य: मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवारों, जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं, को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना।
- ◆ **गरीबी रेखा से नीचे (BPL)** जीवन यापन करने वाले ग्रामीण लोगों को आवास इकाइयों के निर्माण तथा मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना।
- **लाभार्थी:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूर और गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएँ या उनके निकट संबंधी, पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक।

छत्तीसगढ़ में साइबर धोखाधड़ी रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ में कुल 168 करोड़ रुपये के **साइबर अपराध** के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 5.2 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, यह जानकारी उपमुख्यमंत्री ने **विधानसभा** सत्र के दौरान सदन को दी।

मुख्य बिंदु

- **साइबर धोखाधड़ी:** यह एक प्रकार का **साइबर अपराध** है, जिसका उद्देश्य किसी संस्था से पैसे (या अन्य मूल्यवान संपत्ति) चुराना है। इसमें धोखाधड़ी करने के लिये ऑनलाइन साधन (इंटरनेट आधारित) का उपयोग करना शामिल है।
- **साइबर धोखाधड़ी के प्रकार:**

साइबर धोखाधड़ी	विवरण
फ़िशिंग	फ़िशिंग में ऐसे ई-मेल शामिल होते हैं, जो विश्वसनीय स्रोतों से आते प्रतीत होते हैं, जो उपयोगकर्ताओं को ऐसे लिंक पर क्लिक करने के लिये प्रेरित करते हैं जो उन्हें नकली वेबसाइटों पर ले जाते हैं और हमलावर संवेदनशील विवरण जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर आदि प्राप्त कर लेते हैं।
मैलवेयर	मैलवेयर का उपयोग व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिये किया जाता है, जिससे साइबर अपराधी पीड़ित के कंप्यूटर पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



रैसमवेयर	रैसमवेयर पीड़ित की फ़ाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और डिक्риप्शन के लिये भुगतान की मांग करता है। उदाहरण के लिये, 2016 में वानाक्राई हमला।
साइबर-धमकी	साइबर-धमकी में किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा पहुँचाना, कुछ भी कहने या कराने के लिये दबाव डालना शामिल है।
साइबर जासूसी	साइबर जासूसी किसी सार्वजनिक या निजी संस्था के नेटवर्क को लक्ष्य बनाकर वर्गीकृत डेटा, निजी सूचना या बौद्धिक संपदा तक पहुँच प्राप्त करती है।
व्यावसायिक ई-मेल समझौता (BEC)	घोटालेबाज़, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों या कर कार्यालय के सदस्यों का रूप धारण करने के लिये वैध ई-मेल खातों को हैक कर लेते हैं, जिसे सफेदपोश अपराध माना जाता है।
डेटिंग हुडविंक्स	हैकर्स संभावित साझेदार के रूप में प्रस्तुत होने और व्यक्तिगत डेटा तक पहुँच प्राप्त करने के लिये डेटिंग वेबसाइटों, चैट रूम और ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स का उपयोग करते हैं।

- **प्रत्येक ज़िले में साइबर सेल:** छत्तीसगढ़ के सभी पाँच संभागों में अब प्रत्येक ज़िले में एक साइबर सेल है और ऐसे मामलों से निपटने के लिये पुलिस थानों को उन्नत किया गया है।
- ◆ सभी ज़िला पुलिस स्टेशनों को साइबर पुलिस स्टेशनों में उन्नत किया जा रहा है तथा विशेषज्ञ कर्मचारियों को राष्ट्रीय केंद्रों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- **निवेश:** राज्य सरकार ने एक साइबर भवन के निर्माण में 2.77 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो एकीकृत फोरेंसिक डिवाइस, मोबाइल फोरेंसिक किट और डिस्क स्टोरेज सिस्टम सहित अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है।
- ◆ ये तकनीकी प्रगति राज्य में साइबर अपराध और धोखाधड़ी से निपटने के लिये चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं।
- **साइबर धोखाधड़ी में वृद्धि:** वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध बढ़ रहा है, पिछले साल डिजिटल लेन-देन 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। जैसे-जैसे डिजिटल लेन-देन बढ़ रहा है, साइबर धोखाधड़ी की घटनाएँ भी बढ़ रही हैं।

छत्तीसगढ़ में महिला पंचायत की जगह प्रॉक्सी शपथ

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम ज़िले के परसवाड़ा ग्राम पंचायत में छह नवनिर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों के पतियों (**प्रधान पति**) ने कथित तौर पर उनकी जगह शपथ ली।

मुख्य बिंदु

- **प्रधान पति:** यह भारत में पंचायतों (ग्राम परिषदों) में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पतियों का वर्णन करने के लिये प्रयुक्त एक बोलचाल का शब्द है, जो अनौपचारिक रूप से अपनी पत्नियों (वास्तविक पंचायत प्रतिनिधियों) की ओर से सत्ता का प्रयोग करते हैं।
- ◆ यह घटना सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों के कारण उत्पन्न होती है, जहाँ महिलाओं के आधिकारिक पदों पर रहने के बावजूद, उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य निर्णय लेते हैं और **प्रशासनिक कर्तव्यों** का निर्वहन करते हैं।
- **शपथ ग्रहण विवाद :** सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर छह नवनिर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों के पति उनकी जगह शपथ लेते नजर आ रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ इस पर पंडरिया जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मामले की जाँच करने के निर्देश दिये गए हैं। उन्होंने बताया कि जाँचरिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
- अनियमित शपथ-ग्रहण : पंचायत सचिव ने कथित तौर पर वास्तविक प्रतिनिधियों के बजाय छह निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पतियों को शपथ दिलाई।
- जन आक्रोश : स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण का उल्लंघन बताया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई में विफलता भविष्य में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे सकती है।

पंचायती राज संस्थाओं (PRI) का शासन

- राज्य विषय:
 - ◆ स्थानीय शासन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, तथा पंचायती राज संस्थाएँ संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के अनुसार कार्य करती हैं।
- संवैधानिक ढांचा:
 - ◆ 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना की और महिलाओं के लिये 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया, जिसे बाद में 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ाकर 50% कर दिया गया।
 - ◆ अनुच्छेद 243डी पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण का प्रावधान करता है।
 - ◆ संविधान का अनुच्छेद 40, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना करने तथा उन्हें स्वशासी इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिये आवश्यक शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करने का अधिकार देता है।
- अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पेसा) अधिनियम, 1996, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और जनजातीय संस्कृति और आजीविका की रक्षा के लिये विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है।

नई माओवादी पुनर्वास नीति

चर्चा में क्यों ?

12 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिये एक नई पुनर्वास नीति को मंजूरी दी, जिसमें उनके लिये वित्तीय सहायता, शिक्षा, रोज़गार और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्य बिंदु

- नई माओवादी पुनर्वास नीति:
 - ◆ छत्तीसगढ़ नक्सल आत्मसमर्पण/पीड़ित सहायता एवं पुनर्वास नीति-2025, 2023 नीति का स्थान लेगी।
 - ◆ यह नीति आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को वित्तीय सहायता, शिक्षा, रोज़गार और सुरक्षा प्रदान करती है।
 - ◆ यह विशेष योजनाएँ स्व-रोज़गार और कौशल विकास में सहायता करेगी, जिससे समाज में पुनः एकीकरण सुनिश्चित होगा।
 - ◆ इससे माओवादी हिंसा के पीड़ितों को सहायता और पुनर्वास में सहायता मिलेगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र (SWIC) की स्थापना:
 - ◆ मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक जल संसाधन प्रबंधन के लिये SWIC की स्थापना को मंजूरी दी।
 - ◆ सहयोग के लिये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।
 - ◆ SWIC वर्षा, भूजल गुणवत्ता, जलाशय स्तर आदि पर डेटा एकत्रित, विश्लेषण और भंडारण करेगा।
 - ◆ राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केन्द्र (NWIC) नीति निर्माण और रणनीतिक निर्णयों के लिये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ इस पहल का समर्थन करेगा।
- प्रमुख विधायी विधेयकों का अनुमोदन:
 - ◆ छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025
 - ◆ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक-2025
 - ◆ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक-2025
- मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना का शुभारंभ:
 - ◆ इस योजना का उद्देश्य युवाओं को शासन और नीति कार्यान्वयन में शामिल करना है।
 - ◆ इससे राज्य में सुशासन प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिलेगा।

सुदूर सीआरपीएफ बेस पर पहला मोबाइल टावर

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा ज़िले के सुदूर क्षेत्र टेकुलागुडेम गाँव में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) शिविर के अंदर पहला मोबाइल फोन टावर स्थापित किया गया।

- यह पहल मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद (LWE) को समाप्त करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है।

मुख्य बिंदु

- BSNL मोबाइल टावर चालू:
 - ◆ भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) का मोबाइल टावर इस क्षेत्र में पहली मोबाइल कनेक्टिविटी सुविधा है, जिससे ग्रामीणों और सुरक्षाकर्मियों दोनों को लाभ होगा।
 - ◆ यह टावर टेकुलागुडेम और आसपास के गाँवों, जिनमें तिममापुरम, जोनागुडा और पुवर्ती शामिल हैं, को सेवा प्रदान करेगा।
 - यह गाँव सुकमा ज़िले में है, जो नक्सल हिंसा से बुरी तरह प्रभावित है और बस्तर क्षेत्र के बीजापुर से इसकी सीमा लगती है।
- ग्रामीणों के लिये विशेष पहल:
 - ◆ टावर को चालू करने के लिये बीएसएनएल के अधिकारी सुकमा मुख्यालय और रायपुर से आए।
 - ◆ स्थानीय आबादी के लिये सिम कार्ड वितरित करने और सक्रिय करने के लिये एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

- प्रारंभ और विकास:
 - ◆ CRPF की स्थापना वर्ष 1939 में रियासतों में राजनीतिक उथल-पुथल और अशांति के जवाब में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ वर्ष 1949 में इस बल का नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया।
- ◆ तत्कालीन गृह मंत्री **सरदार वल्लभ भाई पटेल** ने CRPF के लिये एक बहुमुखी भूमिका की कल्पना की थी तथा इसके कार्यों को नव स्वतंत्र राष्ट्र की उभरती जरूरतों के साथ संरेखित किया था।
- विशेष इकाइयाँ:
 - ◆ CRPF में कई विशेष इकाइयाँ हैं, जिनमें रैपिड एक्शन फोर्स (RAF), कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा), वीआईपी सुरक्षा विंग और महिला बटालियन शामिल हैं।
- उपलब्धियाँ और योगदान:
 - ◆ CRPF ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्थलों पर हमलों को विफल किया है, पंजाब और त्रिपुरा में उग्रवाद को नियंत्रित किया है तथा नक्सलवाद के उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- बहादुरों का सम्मान:
 - ◆ CRPF ने भारी कीमत चुकाई है, जिसके 2,255 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और उन्हें जॉर्ज क्रॉस, **अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र** आदि सहित अलंकरणों से सम्मानित किया गया।

कांग्रे घाटी राष्ट्रीय उद्यान

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित कांग्रे घाटी राष्ट्रीय उद्यान (KVNP) को प्राकृतिक धरोहर श्रेणी के अंतर्गत **विश्व धरोहर स्थलों की अपनी संभावित सूची** में शामिल किया है।

मुख्य बिंदु

- यूनेस्को की अनंतिम सूची में शामिल:
 - ◆ राज्य के मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए **जैवविविधता संरक्षण, जनजातीय संस्कृति संवर्द्धन और इको-पर्यटन** में KVNP की भूमिका पर प्रकाश डाला।
 - ◆ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि **वैश्विक मान्यता से पर्यटन को बढ़ावा** मिलेगा तथा बस्तर और छत्तीसगढ़ को प्रतिष्ठा मिलेगी।
- यूनेस्को मानदंड:
 - ◆ KVNP ने तीन महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर यूनेस्को सूची के लिये अर्हता प्राप्त की:
 - प्राकृतिक सौंदर्य - परिदृश्य, झरने और घाटियाँ।
 - भूवैज्ञानिक महत्त्व - अद्वितीय चट्टान संरचनाएँ और चूना पत्थर की गुफाएँ।
 - जैवविविधता - दुर्लभ प्रजातियों सहित समृद्ध वनस्पति और जीव।
- प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:
 - ◆ राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधन ने संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप यूनेस्को ने KVNP को अस्थायी सूची में शामिल करने का निर्णय लिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान

● स्थिति:

- ◆ यह छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले के जगदलपुर में गोदावरी नदी की सहायक नदी खोलाबा के तट पर स्थित है।
- ◆ इसका नाम कांगेर नदी के नाम पर रखा गया है, जो इसके मध्य से बहती है।
- ◆ इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
- ◆ संपूर्ण उद्यान एक कोर क्षेत्र है, जिसमें कोई बफर जोन नहीं है।

● स्थलाकृति:

- ◆ इसमें पठार, घाटियाँ, खड़ी ढलानें और जलधाराएँ सहित विविध परिदृश्य मौजूद हैं।
- ◆ इसमें तीन प्रसिद्ध चूना पत्थर की गुफाएँ हैं - कुटुम्बसर, कैलाश और दंडक - जो स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स के लिये प्रसिद्ध हैं।
 - स्टैलेक्टाइट एक हिमखंड के आकार की संरचना है जो गुफा की छत से लटकती है और गुफा की छत से टपकने वाले पानी से खनिजों के अवक्षेपण से बनती है। अधिकांश स्टैलेक्टाइट्स के सिरे नुकीले होते हैं।
 - स्टैलेग्माइट खनिज जमा का ऊपर की ओर बढ़ता हुआ टीला है जो गुफा के तल पर टपकने वाले पानी से बना है। ज्यादातर स्टैलेग्माइट्स के सिरे गोल या चपटे होते हैं।
- ◆ यहाँ तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, जो एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है तथा यहाँ बड़ी संख्या में जनजातीय लोग रहते हैं।
- ◆ इसमें ड्रिपस्टोन और फ्लोस्टोन संरचनाओं के साथ भूमिगत चूना पत्थर की गुफाएँ हैं।

● वनस्पति:

- ◆ मिश्रित आर्द्र पर्णपाती वनों की विशेषता है।
- ◆ प्रचुर मात्रा में पेड़ प्रजातियों में साल, सौगाँव, सागौन और बाँस शामिल हैं।

● जीव-जंतु:

- ◆ प्रमुख स्तनधारी: बाघ, चूहा हिरण, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, सांभर, चीतल, भौंकने वाला हिरण, लंगूर, सियार, रीसस मकाक और उड़ने वाली गिलहरी।
- ◆ वायवीय जीवसमूह: सामान्य पहाड़ी मैना, लाल जंगली मुर्गी, चित्तीदार उल्लू, रैकेट-पूँछ वाले ड्रोंगो और तोते।

यूनेस्को की संभावित सूची

- यूनेस्को की अस्थायी सूची उन संपत्तियों की सूची है, जिन पर प्रत्येक राज्य पक्ष नामांकन के लिये विचार करना चाहता है।
- ◆ यूनेस्को के परिचालन दिशानिर्देश, 2019 के अनुसार, किसी भी स्मारक/स्थल को अंतिम नामांकन डोजियर के लिये विचार किये जाने से पहले एक वर्ष के लिये अनंतिम सूची में रखना अनिवार्य है।
- ◆ नामांकन हो जाने के बाद इसे विश्व धरोहर केंद्र (WHC) को भेज दिया जाता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



छत्तीसगढ़ खनिज राजस्व में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ के कुशल खनिज संसाधन निष्कर्षण ने राज्य के गठन के बाद से राज्य के खनिज राजस्व में अभूतपूर्व 30 गुना वृद्धि की है, जो 2023-24 में 13,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है।

मुख्य बिंदु

- **खनिज ब्लॉकों की सफल ई-नीलामी:**
 - ◆ छत्तीसगढ़ ने 44 खनिज ब्लॉकों के लिये ई-नीलामी आयोजित की है, जिससे संसाधन आवंटन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हुई है।
 - ◆ भारत की पहली लिथियम ब्लॉक नीलामी छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई, जिसमें कोरबा ज़िले के कटघोरा लिथियम ब्लॉक को साउथ मैकी माइनिंग कंपनी को 76% प्रीमियम पर आवंटित किया गया।
 - ◆ सुकमा और कोरबा ज़िलों में लिथियम की खोज जारी है तथा अधिकारियों ने आशाजनक भंडार की सूचना दी है।
- **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन:**
 - ◆ महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व को समझते हुए, भारत सरकार ने जनवरी 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया।
 - ◆ इस पहल के अनुरूप, छत्तीसगढ़ ने अन्वेषण को प्राथमिकता दी है तथा महत्वपूर्ण एवं गहरे खनिजों पर चल रही 56 परियोजनाओं में से 31 पर ध्यान केंद्रित किया है।
- **लौह अयस्क खनन और ई-नीलामी विस्तार:**
 - ◆ बैलाडीला क्षेत्र एक प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडारों में से एक है।
 - ◆ राज्य तीन नए लौह अयस्क ब्लॉकों के लिये ई-नीलामी आयोजित कर रहा है, जिसके मार्च 2025 तक समाप्त होने की उम्मीद है।
 - ◆ कांकेर ज़िले में हाहालद्दी लौह अयस्क ब्लॉक अंतिम नीलामी चरण में है।
- **छत्तीसगढ़ का समृद्ध प्राकृतिक संसाधन आधार:**
 - ◆ राज्य में 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, सोना, निकल, क्रोमियम, प्लैटिनम समूह के तत्व शामिल हैं।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM)

- **उद्देश्य:** NCMM का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना और उच्च तकनीक उद्योगों, स्वच्छ ऊर्जा और राष्ट्रीय रक्षा के लिये आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है।
- ◆ मिशन में खनिज अन्वेषण, खनन, लाभकारीकरण, प्रसंस्करण और जीवन के अंतिम उत्पादों से पुनर्प्राप्ति सहित सभी चरण शामिल होंगे।
- ◆ यह मिशन देश के भीतर और इसके अपतटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को तीव्र करेगा।
- **दृष्टिकोण:** NCMM विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर काम करते हुए “संपूर्ण सरकार” दृष्टिकोण अपनाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

- ◆ महत्वपूर्ण खनिजों के लिये खनन परियोजनाओं में तेजी लाने के लिये फास्ट-ट्रैक अनुमोदन प्रक्रिया स्थापित की जाएगी।
- **खनिजों का भण्डारण:** महत्वपूर्ण खनिजों के भण्डारण के लिये NCMM के प्रावधान यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत के पास भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिये पर्याप्त भंडार उपलब्ध हो।
- **अंतर्राष्ट्रीय रणनीति:** भारतीय कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार संबंध बनाने के लिये प्रोत्साहित करती है।
- **बुनियादी ढाँचा:** मिशन खनिज प्रसंस्करण पार्क स्थापित करेगा, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देगा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के लिये उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण सहित संबंधित प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान का समर्थन करेगा।
- ◆ वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से उद्योगों को भारत में प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
- ◆ महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में स्टार्टअप्स और **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME)** को वित्तपोषित करने के लिये व्यक्तियों, स्टार्टअप्स और MSME में नवाचारों को बढ़ावा देने (PRISM) पहल का विस्तार किया गया।

बस्तर में 30 माओवादी मारे गए

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में **सुरक्षा बलों** ने दो अभियानों में 30 कथित **माओवादियों** को मार गिराया।

मुख्य बिंदु

- **मुठभेड़ के बारे में:**
 - ◆ सुरक्षा बलों ने गंगालूर पुलिस थाना क्षेत्र में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया।
 - ◆ गोलीबारी बंद होने के बाद सुरक्षाकर्मियों ने 26 माओवादियों के शव तथा भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया।
 - ◆ कांकर-नारायणपुर सीमा पर ज़िला रिजर्व गार्ड (DRG) और **सीमा सुरक्षा बल (BSF)** की संयुक्त टीम और माओवादियों के बीच एक अलग मुठभेड़ हुई।
- **सरकार की प्रतिक्रिया:**
 - ◆ **केंद्रीय गृह मंत्री** ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में इस अभियान को एक “बड़ी सफलता” बताया।
 - ◆ उन्होंने सरकार की शून्य सहनशीलता की नीति दोहराते हुए कहा कि भारत 31 मार्च, 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा।

ज़िला रिजर्व गार्ड (DRG)

- ज़िला रिजर्व गार्ड (DRG) छत्तीसगढ़ में एक विशेष पुलिस इकाई है, जिसे 2008 में **माओवादी** हिंसा से निपटने के लिये स्थापित किया गया था।
- इसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित कार्मिक शामिल होते हैं जो प्रभावित जिलों में माओवाद-विरोधी अभियान चलाते हैं, तलाशी और जब्ती करते हैं तथा खुफिया जानकारी एकत्र करते हैं।
- माओवादी विद्रोह का सामना करने के लिये DRG **केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)** जैसे अन्य सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



सीमा सुरक्षा बल (BSF)

- BSF की स्थापना वर्ष 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद की गई थी।
- यह गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs - MHA) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत संघ के सात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है।
- ◆ अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं: असम राइफल्स (AR), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और सशस्त्र सीमा बल (SSB)
- 2.65 लाख पुलिस बल पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर तैनात हैं।
- ◆ इसे भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा (LoC) पर भारतीय सेना के साथ तथा नक्सल विरोधी अभियानों में तैनात किया जाता है।
- BSF अपने जलयानों के अत्याधुनिक बेड़े के साथ अरब सागर में सर क्रीक और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा की रक्षा कर रहा है।
- यह प्रत्येक वर्ष अपनी प्रशिक्षित जनशक्ति की एक बड़ी टुकड़ी भेजकर संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में समर्पित सेवाओं का योगदान देता है।

‘माओवाद मुक्त’ पंचायतों के लिये विशेष प्रोत्साहन

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर में माओवादियों के आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित करने के लिये एक योजना शुरू की है, जिसके तहत “माओवाद-मुक्त” पंचायतों को निर्माण परियोजनाओं के लिये 1 करोड़ रुपए और अन्य लाभ प्रदान किये जाएंगे।

मुख्य बिंदु

- माओवादी आत्मसमर्पण आवश्यकता:
 - ◆ राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने घोषणा की कि एलवाड पंचायत अभियान के तहत पंचायत को नक्सल गतिविधियों में शामिल सभी निवासियों का आत्मसमर्पण सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद गाँव माओवाद मुक्त घोषित करने के लिये प्रस्ताव पेश कर सकता है।
- माओवाद मुक्त पंचायतों के लिये प्रोत्साहन:
 - ◆ निर्माण परियोजनाओं के लिये 1 करोड़ रुपए की तत्काल मंजूरी।
 - ◆ नेटवर्क पहुँच में सुधार के लिये मोबाइल टावरों की स्थापना या निकटवर्ती टावरों से सिग्नल ट्रांसमिशन।
 - ◆ पंचायत तक विद्युत् लाइनों का विस्तार तथा ग्रिड कनेक्शन स्थापित होने तक अस्थायी उपाय के रूप में सौर प्रकाश व्यवस्था।
- ओडीएफ गाँवों और पुनर्वास नीति के साथ तुलना:
 - ◆ उपमुख्यमंत्री ने इस पहल की तुलना खुले में शौच मुक्त (ODF) गाँव अभियान से की तथा सामूहिक सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ उन्होंने छत्तीसगढ़ नक्सल आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 के प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें शामिल हैं:
 - कौशल विकास: आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिये प्रशिक्षण।
 - आवास और भूमि आवंटन: पीएम आवास योजना के तहत।
 - वित्तीय सहायता: पुनर्वास के लिये अतिरिक्त राहत उपाय।

माओवाद

- परिचय:
 - ◆ माओवाद माओ त्से तुंग द्वारा विकसित साम्यवाद का एक रूप है। यह सशस्त्र विद्रोह, जन-आंदोलन और रणनीतिक गठबंधनों के संयोजन के माध्यम से राज्य सत्ता पर कब्जा करने का सिद्धांत है।
 - माओ ने इस प्रक्रिया को 'दीर्घकालिक जनयुद्ध' कहा, जिसमें सत्ता पर कब्जा करने के लिये 'सैन्य लाइन' पर जोर दिया जाता है।
- माओवादी विचारधारा:
 - ◆ माओवादी विचारधारा का केंद्रीय विषय राज्य सत्ता पर कब्जा करने के साधन के रूप में हिंसा और सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग करना है।
 - माओवादी उग्रवाद सिद्धांत के अनुसार, 'हथियार रखने पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता'।
- भारतीय माओवादी:
 - ◆ भारत में सबसे बड़ा और सबसे हिंसक माओवादी संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) है जिसका गठन वर्ष 2004 में हुआ था।
 - ◆ CPI (माओवादी) और उसके अग्रणी संगठनों को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया।
 - ◆ फ्रंट ऑर्गनाइजेशन मूल माओवादी पार्टी की शाखाएँ हैं, जो कानूनी उत्तरदायित्व से बचने के लिये अलग अस्तित्व का दावा करती हैं।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट: